आधार हैं और शारीरिक क्षमता तथा शैक्षिक योग्यता के संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोनू): (क) और (ख) देश में सेना भर्ती केन्द्रों की कुल संख्या 130 है। इसमें 13 मुख्यालय भर्ती जोन, 71 शाखा भर्ती कार्यालय और 46 प्रशिक्षण केन्द्र हैं। सेना में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और केन्द्रवार की गई भर्ती के ब्यौरे अनुपत्र [देखिए परिशिष्ट 179, अनुपत्र संख्या 13] विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या विभिन्न जोनल भर्ती कार्यालयों और केन्द्रों की रिक्तियों का पता लगाने/आबंटित करने का आधार होती है। भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या में वे पुरुष शामिल किए जाते हैं जो निर्धारित गुणता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इसकी गणना प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र की पुरुष जनसंख्या के 10% के बराबर की जाती है। सेना में भर्ती संबंधी निर्धारित न्यूनतम शारीरिक मानक और शैक्षणिक अर्हताएं अनुपत्र में दिए गए हैं।

नौसेना के 20 भर्ती केन्द्र हैं जो देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। नौसेना में पिछले तीन वर्षों में की गई भर्ती के राज्यवार ब्यौरे अनुपत्र में संलग्न हैं। केन्द्रवार की गई भर्ती के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और शीघ्र ही वे माननीय सांसद को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है और किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए कोई भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या नियत नहीं की गई है। नौसेना में प्रति-वर्ष भरे जाने वाले रिक्त पदों का आकलन, सेवानिवृत्त तथा अन्य कारणों से रिक्त होने वाले अनुमानित पदों, योजनानुसार की जाने वाली वृद्धि और नौसेना की प्रशिक्षण क्षमता के आधार पर की जाती है। नौसेना में चयन के लिए अपेक्षित शारीरिक मानदण्ड और शैक्षणिक अर्हताएं अनुपत्र में दिए गए हैं।

देश में इस समय 13 वायुसैनिक चयन केन्द्र हैं। वायुसेना में पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई भर्ती का राज्यवार और केन्द्रवार ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है और किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए कोई भर्ती योग्य पुरूष जनसंख्या नियत नहीं की गई है। प्रति वर्ष वायुसेना में भरे जाने वाले रिक्त पदों का आकलन सम्भावित सेवा-निवृत्त, समयपूर्व सेवामुक्ति/मृत्यु और पदोन्नतियों के कारण होने वाली रिक्तियों के आधार पर की जाती है। वायुसेना में चयन के लिए निर्धारित शारीरिक मानक और शैक्षणिक अर्हताएं अनुपत्र में दी गई है।

Integrated water plan

575. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether a commission for integrated water plan has been set up;

(b) if so, the terms of reference and other details; and

(c) by when the commission is likely to submit its feasibility report in regard to linking of river waters?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached. (*See* below)

(c) The Commission is likely to submit its report in 2 years time.

Statement

Integrated Water Plan.

1. This Ministry has set up a National Commission for Integrated Water Resources Development Plan with the following composition:—

1.	Shri C.H. Hanumantha Rao Ex-Member, Planning Commission	: Chairman
2.	Dr. S.R. Hashim Member, Planning Commission	: Vice-Chairman
3.	Shri V. Ramachandran Ex-Chief Secretary Govt. of Kerala Trivandrum.	: Member
4.	Dr. V.S. Vyas (Economist) Director, Institute of Development Studies, 8-B Jhalana Institutional Area, Jaipur- 302 004.	: Member

5. Dr. D.N. Tewari, Ex-Chancellor, F.R.I. (Deemed University) Dehradun (UP). : Member

6. Shri S.P. Prakash, Ex-Engineer-in-Chief, Delhi Water Supply & Sewage Disposal Undertaking. : Member

7. Shri C.C. Patel Ex-Secretary (WR) Govt. of India. : Member

8. Dr.Bharat Singh Vice-Chancellor (Retd.) University of Roorkee. : Member

9. Shri S.P. Caprihan Engineer-in-Chief (Retd) Government of M.P. : Member

10. Director General, National Water Development Agency (NWDA), New Delhi. : Member Secretary

There is also a provision to co-opt other experts for assisting the Commission.

2. The terms of reference of the Commission are as under:—

(i) To prepare an Integrated Water Plan for development of water resources for Drinking, Irrigation, Industrial, Flood Control and Other uses;

(ii) To suggest modalities for transfer of surplus water to water-deficit basin by inter-linking of rivers for achieving the above objectives;

(iii) To identify important On-going Projects as well as New Projects which should be completed on priority basis together with pashing?

(iv) Identify a technological and interdisciplinary research plan for the water sector with a view maximise the benefits.

(v) To suggest physical and financial resource generation strategies for the water sector;

(vi) Any other related issue.

Issues discussed in the Inter-State Council Meeting

576. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the various issues discussed in the Inter-State Council meeting held in New Delhi in October, 1996;

(b) the opinion expressed by different Chief Ministers in that meeting;

(c) the steps taken by Government to implement various recommendations made by the Inter-State Council meeting; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (d) The following was the agenda for the second meeting of the Inter-State Council held on 15.10.96:—

(1) Consideration of 179 recommendations of Sarkaria Commission on which there was a consensus in the Sub-Committee of the Inter-State Council and adoption of resolutions;

(2) Methodology for examination of 44 recommendations of Sarkaria Commission on Centre-State Financial Relations, 11 recommendations on which there was no consensus in the Sub-Committee and 1 recommendations relating to Centre-State relations in the sphere of education;

(3) Methodology for examination of the recommendations of Sarkaria Commission relating to Emergency Provision including Article 356; and

(4) Appointment of High Level Committee.